

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग,
(नीति शाखा)
व्यापार भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002

विधान सभा प्रश्न संख्या 134 (अतारांकित)

दिनांक -09-08-2017

प्रश्नकर्ता : श्री एस के बग्गा

क्या व्यापार एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	पिछले वित्त वर्ष 2016-17 एवं चालू वित्त वर्ष 2017-18 में (दिनांक 30-06-2017 तक) कितने व्यापारियों को रिफण्ड दिए गए हैं	पिछले वित्त वर्ष 2016-17 में डीवैट के अर्न्तगत 26190 रिफण्ड आर्डर का ई0सी0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है। चालू वित्त वर्ष में जून, 2017-18 तक 9186 रिफण्ड आर्डर का ई0सी0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है।
ख).	पिछले वित्त वर्ष 2016-17 एवं चालू वित्त वर्ष 2017-18 में (दिनांक 30-06-2017 तक) कितना एमाउन्ट व्यापारियों को रिफण्ड दिए गए हैं ;	पिछले वित्त वर्ष में 2016-17 में डीवैट के अर्न्तगत कुल 826,47,03,859/- रू0 का ई0सी0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है। चालू वित्त वर्ष में जून, 2017-18 तक कुल 359,24,09,538/-रू0 का भुगतान ई0सी0एस0 के माध्यम से हुआ है।
ग).	पिछले वित्त वर्ष 2016-17 एवं चालू वित्त वर्ष 2017-18 में (दिनांक 30-06-2017 तक) रिफण्ड एमाउन्ट पर कितना ब्याज दिया गया है।	यह सूचना विभाग द्वारा एकत्रित की जा रही है।
घ).	चालू वित्त वर्ष 2017-18 में (दिनांक 30-06-2017 तक) वैट के कितने रजिस्ट्रेशन रद्द किए गये हैं ? इसका क्या कारण है ;	चालू वित्त वर्ष 2017-18 में (दिनांक 30-06-2017 तक) वैट के 6288 रजिस्ट्रेशन रद्द किए गये हैं। डी वैट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है।
ड).	अब 01-07-2017 से जीएसटी एक्ट आ गया है। जीएसटी समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जिससे व्यापारियों की समस्या का हल हो ?	1. व्यापारियों की समस्याओं को सुनने एवं उनके हल के लिए व्यापार एवं कर विभाग के प्रथम तल पर एक आधुनिक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है, जहाँ पर प्रातः 9 बजे से शाम के 6:00 बजे तक सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी तथा उनके मातहत कर्मचारी, व्यापारियों की परेशानी सुनते हैं तथा उनका समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त- दूरभाष सहायता केन्द्र(हेल्प लाईन सेवा) भी उपलब्ध करायी गयी है जो व्यापारियों को यथोचित सलाह एवं मार्गदर्शन करने का कार्य करती है।

	<p>2. इसके अतिरिक्त वार्ड स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी वाहन के साथ निरंतर विभिन्न दिल्ली के बाजारों में जा रहे हैं वहां पर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करते हैं । व्यापारियों को प्रपत्र भी प्रदान किये जाते हैं, जिनमे बहुत सारे प्रश्नों के यथोचित उत्तर होते हैं ।</p> <p>3. सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों को अलग -अलग विषय पर व्यापारियों को सहायता करने हेतु विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है ।</p> <p>4. दिल्ली के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों के लिए जीएसटी सपोर्ट ग्रुप तैयार किया जा रहा है जो मुख्यतः उन व्यापारियों की सहायता करेगें जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । इनमें अधिकतर छोटे व्यापारी हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड से कम है ।</p>
--	--



RAJESH MISHRA, IAS
Special Commissioner
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of NCT of Delhi
Vyapar Bhawan, New Delhi